

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार)
=0=

फाइल नं. 8-12/82/का.प्र.सु./1,

भोपाल, दिनांक 25 मई 1982

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त तंभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय: - गोपनीय चरित्रावली में अंकित प्रतिकूल टिप्पणी को संशुचित करने एवं उसके विरुद्ध प्रस्तुत अभ्यावेदन का निराकरण करने में अनावश्यक क्लेश को टालने बाबत ।

=0=0=0=0=

शासन के ध्यान में लाया गया है कि गोपनीय चरित्रावली में अंकित प्रतिकूल टिप्पणी के विरुद्ध प्रस्तुत अभ्यावेदन पर निर्णय होने में अनावश्यक क्लेश होता है । इस का मुख्य कारण यह बताया गया है कि प्रतिकूल टिप्पणी के विरुद्ध प्राप्त प्रतिकेदनों की जब प्रतिकूल टिप्पणी दर्जकर्ता अधिकारी के पास उनके मत के लिए भेजा जाता है, तब वे अपना मत सम्प्रति के भीतर नहीं भेजते । इस संबंध में आपका ध्यान सामान्य पुस्तक : परिपत्र भूभाषक- ड्रमाक ज्ञात की कठिका (तीन) की ओर आकर्षित किया जाता है जो निम्नानुसार है:-

प्रतिकूल टिप्पणी के विरुद्ध प्राप्त प्रतिकेदनों की जब प्रतिकूल टिप्पणी लिखने वाले अधिकारी के पास उनके मत के लिए भेजा जाता है, तब मत देने वाले अधिकारी को चाहिए कि वह संबंधित प्रतिकेदन पर अपना मत, शासन द्वारा मत प्राप्ति के लिए भेजे गये पत्र की तिथि से, एक माह के भीतर भेज दें । यदि संबंधित अधिकारी किसी कारणवश उत्तर भेजने के लिए

नहीं सक्षम रहते है तो उन्हें अनुसार सम्प्रति के अंतर्गत शासन के

प्राप्त कर लेना चाहिए । परन्तु यदि किसी प्रतिकेदन पर और किसी कारण

से एक माह के भीतर मत प्राप्त नहीं होता है तो शासन यह समझ लेगा कि

मध्यप्रदेश शासन
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग

क्र०सफ 5-5/90/9/49,
प्रति,

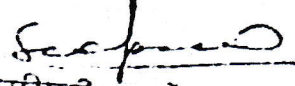
भोपाल, दिनांक 20 नवंबर, 1990

शासन के समस्त विभाग,
समस्त सभागीय आयुक्त,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय:- गोपनीय चरित्रावली में अंकित प्रतिकूल टिप्पणियों के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदन का निराकरण।

शासन के ध्यान में यह लाया गया है कि प्रतिकूल टीकाओं के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदन पर प्रतिकूल टीपकर्ता अधिकारी का मत निर्धारित समयवधि में प्राप्त न होने के कारण प्रकरणों के निराकरण में विलंब होता है। इस संबंध में सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-1-7 की कंडिक्न-तीन एवं इस विभाग के ज्ञापन क्र०सफ 8-12/82/काप्रसु/1, दिनांक 25 मई, 1982 में यह निर्देश दिये गये है कि प्रतिकूल टिप्पणी के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदन पर प्रतिकूल टीपकर्ता अधिकारी को अपना मत शासन द्वारा मत प्राप्त के लिये भेजे गये पत्र की तिथि से एक माह के भीतर भेज देना चाहिये। यदि संबंधित अधिकारी किसी कारणवश उत्तर भेजने के लिये कुछ अधिक समय चाहते हैं तो उन्हें तदनुसार समयवधि के आदेश शासन से प्राप्त कर लेना चाहिये। परंतु यदि किसी अभ्यावेदन पर बगैर किसी कारण के एक माह के भीतर मत प्राप्त नहीं होता तो शासन यह समझ लेगा कि मत भेजने वाले अधिकारी को संबंधित अभ्यावेदन पर कोई मत नहीं देना है और शासन तब अभ्यावेदन प्रस्तुत करने वाले अधिकारी के संबंधित अभ्यावेदन पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही कर सकेगा। परंतु यह देखा गया है कि अधिकार विभागों द्वारा उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही न करने के कारण ऐसे प्रकरण के निपटारे में विलंब होता है।

तो प्रतिकूल टीकाओं के विरुद्ध प्रस्तुत किये गये अभ्यासोद्देश का निराकरण
गुणदोष के आधार पर यथाशीघ्र किया जाय। कृपया इन निर्देशों का कठोर
से पालन सुनिश्चित किया जाय।

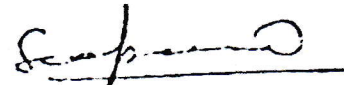

§ स्टीफन खखो §
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आगतिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग

पृ. क्रं. स्फ 5-5/90/9/49,

दिनांक 20 नवम्बर, 1990

प्रतिलिपि :-

- 1§ रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इंदौर।
- 2§ राज्यपाल के सचिव/तैनिक सचिव, मध्यप्रदेश भोपाल
सचिव, लोक आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल
सचिव, विधानसभा सचिवालय, म. प्र. भोपाल।
- 3§ अवर सचिव §स्थापना§, अधीक्षण, अभिलेख, लेखाधिकारी, म. प्र. सचिवालय
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रोपि।


§ स्टीफन खखो §
अवर सचिव